

ट्रंप की ‘‘ग्रीनलैंड’’ पर आधिपत्य जमाने की धमकी से यूरोप में खलबली

वैनेज़ुएला पर सैनिक कार्यवाही के बाद, विश्व ट्रंप की ग्रीनलैंड की धमकी को केवल बड़बोलापन नहीं मान रहा। बल्कि, ट्रंप के गैर जिम्मेवारानापन व ‘‘अनप्रेडिक्टिव सोच’’ की निशानी मान रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस बयान पर, कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल ‘‘हमेशा एक विकल्प’’ है, डेनमार्क ने कड़ी राजनयिक प्रतिक्रिया दी है और नाटो में चिंता की लहर दौड़ गई है। हालांकि वॉशिंगटन का कहना है कि वह सिर्फ सभी विकल्प खुले रख रहा है। ये टिप्पणियाँ आर्कटिक द्वीप को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की अब तक की सबसे आक्रामक अभिव्यक्ति हैं। यह बयान वैनेज़ुएला में लाने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की अब तक की सबसे आक्रामक अभिव्यक्ति हैं। यह बयान वैनेज़ुएला में लाने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की अब तक की सबसे आक्रामक अभिव्यक्ति हैं।

- ग्रीनलैंड, डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा रहा है और डेनमार्क, नाटो का शुरु से सदस्य है. अब ‘‘ग्रीनलैंड’’ पर सैनिक कार्यवाही करना, नाटो के सदस्य के खिलाफ सैनिक आक्रमण है और नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप में अमेरिका की मदद से खड़ा किया गया संगठन है, जिसने यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखी, रूस की तथाकथित आक्रामक सोच की छाया में।
- नाटो के अन्य सदस्यों, जैसे टर्की व स्कैंडिनेवियन देशों ने अमेरिका की धमकी के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
- इन देशों व अन्य यूरोपीय देशों का तर्क है, अमेरिका का हित नाटो सदस्यों में आपसी सहयोग बढ़ाने में है, न कि उन्हें आपस में लड़ा कर नाटो का विघटन करने में।

के बाद आया है, जिससे सहयोगी देशों में अमेरिका की अतिश्रुतता को लेकर चिंता और बढ़ गई है। वाइट हाउस ने ग्रीनलैंड को एक रणनीतिक संपत्ति बताया है, जिसकी अहमियत रूस और चीन के साथ

आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण और बढ़ गई है। अधिकारियों का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ऑपरेशन वैनेज़ुएला बहुत साफ-सुथरी व सर्जिकल सैनिक कार्यवाही थी’

पर, अब मालूम पड़ रहा है कि अमेरिका का यह दावा काफी थोथा व असत्य था, क्योंकि अब सब स्वीकार कर रहे हैं कि कम से कम 80 लोग मारे गए थे, कई सारे घर व मकान तहस-नहस हो गए थे, अमेरिकी बमबारी में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जनवरी। काराकस, वैनेज़ुएला में एक साफ़-सुथरा और सर्जिकल ऑपरेशन करने के अमेरिकी दावों के विपरीत, अब यह साफ हो गया है कि देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण की पूरी कार्रवाई बेहद हिंसक और खून-खराबे वाली थी। कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। इनमें ड्यूटी पर तैनात वैनेज़ुएला और अन्य विदेशी भाड़े के सैनिकों के साथ-साथ वे आम नागरिक भी शामिल हैं, जो गोलीबारी की चपेट में आ गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि सैन्य हमलों में उनके घर तबाह हो गए। वैनेज़ुएला के अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की अंतिम संख्या इससे कहीं

- जैसा कि अब अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि 150 अमेरिकी हवाई जहाजों ने आक्रमण में भाग लिया था, समुद्र के जहाजों, अन्य ट्रकों व ट्रैकों के अलावा। सभी को विशेषकर वैनेज़ुएला को आभास था कि अमेरिका आक्रमण करने वाला है तथा वैनेज़ुएला की आर्मी व वायु सेना तैयार थी लड़ाई के लिए। अतः आसमान में ‘‘डॉंग फ़ाइटर्स’’ हुई व जमीन पर काफी गोलाबारी भी देखी गई थी।
- अमेरिका ने अब ‘‘डिमांड’’ रखी है. वैनेज़ुएला के समक्ष कि वह 50 मिलियन ऑयल दे, अमेरिका को, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने के लिए तथा आमदनी अमेरिका के कोष में जमा होगी तथा थोड़ा बहुत अंश वैनेज़ुएला को भी मिलेगा।

अधिक हो सकती है। बेहद हिंसक, लेकिन प्रभावी बताया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड में जंगली हाथी ने 7 को मारा

चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम), 07 जनवरी। नोवामुंडी प्रखंड के जेटेया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबरिया गांव में 6 जनवरी की रात जंगली हाथी के हमले से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे परिवार के एक सदस्य की भी हाथी

- एक परिवार घर पर सो रहा था, जब हाथी ने अचानक हमला किया।

के हमले में जान चली गई। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि सभी लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी हाथी ने अचानक घर पर हमला कर दिया। इस दौरान परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। बाबरिया गांव में मृतकों की पहचान सनातन मेराल, उनकी पत्नी जॉकी कुई, उनके दो मासूम बच्चों और मोगदा लागुरी (दूसरे परिवार से) के रूप में हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मध्य प्रदेश के गाँवों में एक तिहाई पेयजल पीने योग्य नहीं है’

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जनवरी। मध्य प्रदेश के गाँवों में, पेयजल चुपचाप सार्वजनिक स्वास्थ्य का हथियार बन गया है। केन्द्रीय सरकार के जल जीवन मिशन द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक तिहाई से अधिक पेयजल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, जिससे लाखों लोग अदृश्य, लेकिन जानलेवा प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। 4 जनवरी 2026 को जारी की गई कार्यक्षमता आकलन रिपोर्ट

- केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और कहा गया है कि लाखों लोग भारी प्रदूषण का शिकार हैं।

(फंक्शनलिटी असेसमेंट रिपोर्ट) के अनुसार, मध्य प्रदेश में पानी के केवल 63.3 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता परीक्षणों में पास हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 76 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘चीन, रूस, क्यूबा और ईरान को बाहर निकालो’

ट्रंप ने वैनेज़ुएला की नई अंतरिम सरकार के लिए निर्देश जारी किए

- ट्रंप ने नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगज़ से कहा कि चीन, रूस, ईरान व क्यूबा से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखें।
- ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल उत्पादन में सिर्फ अमेरिका के साथ भागीदारी की जाए और ‘‘हैवी कूड’’ सिर्फ अमेरिका को बेचा जाए।
- ट्रंप के इन दो टूक आदेशों से यह स्पष्ट है कि वैनेज़ुएला का प्रशासन एक तरह से वे ही चला रहे हैं।

बाद, डेल्सी रॉड्रिगज़ ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, जबकि ट्रंप का कहना है कि वे अब इस दक्षिण अमेरिकी देश को नियंत्रित कर रहे हैं। अब, एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन ने वैनेज़ुएला के नए नेतृत्व से कहा है कि उन्हें अपने तेल भंडार से अधिक तेल निकालने की अनुमति तभी दी जायेगी, जब वे उनकी शर्तों का पालन करेंगे। सूत्रों ने कहा, ‘‘सबसे पहले तो, वैनेज़ुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से सम्बंध खत्म करने होंगे और आर्थिक संबंधों को तोड़ना होगा। दूसरे, वैनेज़ुएला को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेल उत्पादन में साझेदारी करने पर सहमत होना होगा और हैवी कूड बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी।’’ ज्ञातव्य है कि चीन लंबे समय से वैनेज़ुएला का करीबी साथी है और यह वैनेज़ुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है।

अमेरिका की आक्रामक वक्तव्यबाजी व हरकतों से ‘‘अमेरिका विरोधी’’ मंच तैयार हो गए हैं

यूरोप, चीन, टर्की के अलावा विश्व भर में लगभग सभी देश अमेरिका द्वारा वैनेज़ुएला में की गई सैन्य कार्यवाही के खिलाफ खुलकर मुखरित हुए हैं

- इस मुद्दे पर ऐसे-ऐसे देश भी एक मंच पर नज़र आए जो आपस में काफी कटुता पाले हुए हैं।
- सब का एक ही मत है कि ग्रीनलैंड के बाशिंदों को ही अन्ततोगत्वा अधिकार प्राप्त हैं कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं या किसी देश का आधिपत्य स्वीकार करना चाहते हैं।
- ग्रीनलैंड के निवासियों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय सुनाया है कि वे स्वाधीन रहना चाहते हैं, किसी अन्य देश में शामिल होकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते। अतः इन लोगों पर इस मुद्दे पर जोर-जबरदस्ती व दबाव डालना गैर-कानूनी व गैर वाजिब है।

यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति और निराशा व्यक्त की है, अमेरिका द्वारा देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक व्यवहार के सभी मानदंडों को खलकर निंदा भी की जा रही है। ग्रीनलैंड यूरोपीय महाद्वीप और अमेरिकी महाद्वीप के बीच स्थित है।

यूरोप ने विशेष रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड वहाँ की जनता का है और किसी और देश का नहीं है और उसकी

सहयोगी की पत्नी ने ग्रीनलैंड का एक नक्शा प्रकाशित किया था, जिसमें पूरे ग्रीनलैंड क्षेत्र पर अमेरिकी ध्वज लहराते हुए दिखाया गया था। कुछ यूरोपीय देशों का कहना है कि डॉनल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के बारे में बयान ‘‘बेहद मुख्तपापूर्ण’’ था। डॉनल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात की ज़रा भी परवा नहीं की, वहां के लोगों ने स्पष्ट रूप से इस योजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को आत्मनिर्णय का अधिकार है, जैसे किसी अन्य देश को होता है।

वैनेज़ुएला पर अमेरिकी आक्रमण और राष्ट्रपति के अपहरण ने दुनिया भर में एंटी-अमेरिका मोर्चे को फिर से सक्रिय कर दिया है। इस कदम ने दुनिया के विभिन्न देशों को अमेरिका के खिलाफ कर दिया है और विभिन्न नेताओं ने इसके पड़ोसी देशों में अमेरिकी कार्रवाई को निंदा की है। तुर्कों के राष्ट्रपति, रेसेप तईप एर्दोग़ान, ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद का सत्र 28 से संभव

नई दिल्ली, 07 जनवरी। केंद्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बुधवार की हुई बैठक में संसद के आगामी बजट सत्र की तारीखों का प्रस्ताव रखा गया।

राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने संसद के बजट

- एक फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश होगा।

सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से करने और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, इन तारीखों पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया जाता है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच अवकाश रखा जाता है, ताकि संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

- कांग्रेस, वामपंथी दलों एवं राजद ने भारत सरकार की हल्की प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने कहा, अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन पर भारत को कड़ा विरोध जताना चाहिए। राजद के मनोज झा ने कहा कि इस सतर्क भाषा के लिए इतिहास भारत को माफ नहीं करेगा। वामपंथी दलों ने भी भारतीय रूख की तीखी आलोचना की।
- लेकिन कांग्रेस के शशि थरुर ने अवश्य सरकार के रूख का बचाव किया और कहा कि भारत ना तो छोटा देश है ना ही कोई राजतंत्र और ट्रूटते अंतर्राष्ट्रीय नियमों के इस दौर में भारत की प्रतिक्रिया लोक लुभावन भाषणों से नहीं बल्कि कूटनीति से प्रभावित होनी चाहिए।
- कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया कूटनीतिक विशेषज्ञ सुहासिनी हैदर ने दी.और कहा, जहाँ कहीं भी अमेरिका की भागीदारी होती है, उस पर हमारी प्रतिक्रिया बेहद सतर्क होती है। यह जरूरी भी है. क्योंकि इस समय भारत-अमेरिका ट्रेड डील संवेदनशील दौर से गुजर रही है।

तक खुद को सीमित रखा। वॉशिंगटन का नाम लेने या उसकी आलोचना करने से वह बचता रहा। इस तरह की चुप्पी

से देश के भीतर राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आलोचकों का कहना है कि इससे

वैश्विक दक्षिण की मुखर आवाज़ के रूप में भारत की साख कमजोर पड़ सकती है।

फायर टेक्नीशियन कोर्स के फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था का निदेशक गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने फायर टेक्नीशियन, फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्‍नाना मोइसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसओजी की टीम चेन्नई से गिरफ्तार कर जयपुर लाई है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, विशेषकर फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती में फर्जी डिग्रियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान संदिग्ध पाया गया। प्रारंभिक स्तर पर पटवारी भर्ती से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की गई, लेकिन वहां गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद जांच का फोकस फायरमैन भर्ती पर किया गया, जहां बीएसएस

निदेशक अरुल ग्‍नाना मोइसन

संस्थान से बैकडेट में डिग्रियां जारी होने के ठोस सबूत सामने आए। एसओजी ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पृष्ठताछ के आधार पर हिंडीन (करोली) स्थित एएस फायर सेप्टी इंस्टीट्यूट के संचालक श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में सामने आया कि यह संस्थान बीएसएस से एंफिलिएटेड है। इसके बाद एसओजी ने बीएसएस के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली, जहां बड़ी संख्या में बैकडेट में जारी की गई डिग्रियां और प्रमाण-पत्रों से

■ **फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्‍नाना मोइसन को गिरफ्तार किया**

जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। सबूत जुटाने के बाद कोर्ट से वारंट प्राप्त कर बीएसएस के निदेशक अरुल ग्‍नाना मोइसन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया।

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान को यूजीसी या किसी भी वैधानिक संस्था से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद यह संस्थान वॉकेशनल कोर्स के नाम पर फायरमैन, फायर टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन सहित कई कोर्सेज की डिग्रियां जारी कर रहा था।

जांच में सामने आया कि बीएसएस ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हुए देशभर में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। संस्था से करीब 1० हजार इंस्टीट्यूट जुड़े, जिनमें से लगभग 7 हजार अभी सक्रिय हैं। इन

संस्थानों और दलालों के माध्यम से हजार से अधिक कोर्सेज की डिग्रियां ऑन-डिमांड जारी की जाती थीं।पड़ताल में यह भी सामने आया कि हर इंस्टीट्यूट का एक दलाल होता था, जो अभ्यर्थियों को झंसे में लेकर उनकी जानकारी बीएसएस कार्यालय भेजता था। इसके बाद मांगी गई तारीख के अनुसार बैक डेट में डिग्री और प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते थे।एसओजी अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पृष्ठताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

एसओजी ने आमजन और नियोजक संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी डिग्री या प्रमाण-पत्र के आधाार पर चयन से पहले उसका पूर्ण और विधिवत सत्यापन अवश्य करें।

ड्रोन व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में 1० जनवरी 2०26 को प्रस्तावित वीवीआईपी के आगमन कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था को प्राविात होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अकादमी क्षेत्र के आसपास ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

महिंद्रा की एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का अनावरण

जयपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में होटल जयपुर मैरियट में अपनी दो नई दमदार एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का भव्य लॉन्च किया। यह कार्रकम बेहद शानदार रहा, जिसमें मौजूदा और नए ग्राहकों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया।

■ **इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं**

लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, करण गहलोत व आराधना गहलोत, ऑटोवर्ल्ड के असुपम सांखला तथा निखित शाह, आरएसएम महिंद्रा एंड महिंद्रा व अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में दोनों वाहनों का अनावरण किया गया, जिसके बाद ग्राहकों ने इनकी विशेषताओं को करीब से देखा और आनंद लिया। एक्सयूवी7एक्सओ के इस नए मॉडल की शुरुआती क्रीमव पेडोल व्हेरीएंट के लिए 13.66 लाख रुपए और डीजल व्हेरीएंट के लिए 14.96 लाख



लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, आराधना गहलोत ने किया ।

रुपए रखी गई है। ये क्रीमते पहले 40,000 ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम हैं। नई एक्सयूवी7एक्सओ को पहले से ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन, अपडेटेड केबिन और कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं।

नई एक्सयूवी7एक्सओ को ग्राहक छह व्हेरीएंट्स में से चुन सकते हैं, जिसमें , 3, 5, 7, 7 और 7 शामिल हैं, जो चार इंजन ऑप्शन में आते हैं। इसके अलावा, इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

महिंद्रा की ई-एसयूवी लाइनअप में 9, 6 और 4०0 के साथ शामिल हो गया है। क्रीमव 19.95 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

महिंद्रा एक्सईवी9एस का डिज़ाइन इसे बाकी एसयूवीज़ से अलग बनाता है। इसमें एक ब्लैक-आउट ग्रिल, एल आकार के एलईडी डीआरएलएस, व्हिंकल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और प्रंट पेंसिल्यार पर एक पिक्सल स्टायल एलईडी लाइट बार मिलता है।

■ **राजस्थान में 10 जनवरी से कांग्रेस का हल्लाबोल**

जयपुर। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना "मनरेगा" को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी सरकार द्वारा योजना का नाम बदलकर वीबी-जी-राम-जी करने और इसमें किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक के विरोध प्रदर्शनों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है।

कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार नाम बदलकर और नियमों में बदलाव कर इस ऐतिहासिक योजना को कमजोर करना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की रणनीति बनाई है।

जहां एक तरफ कांग्रेस मनरेगा बचाओं के नारे के साथ सड़कों पर उतर रही है। वहीं बीजेपी ने भी वीबी-जी-राम-जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है।

आने वाले दिनों में राजस्थान की



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर द्वारा कार्यकर्ता सुनवाई आयोजित का

उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी भी कार्यकर्ता की समस्या लंबित न रहे। मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर ने बताया कि आज की सुनवाई में करीब 150 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश तबादलों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई जैसे कार्यक्रम सरकार और संगठन के बीच

सेतु का कार्य करते हैं और जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार कार्यकर्ताओं की भूमिका को सर्वोपरि मानते हुए ऐसी सुनवाईयों के माध्यम से पारदर्शी एवं सेवेदनशील प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं संगठन स्तर

पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने और संगठन को मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ता सुनवाई में प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी उपस्थित रहे।

आरपीएससी सचिव बताए नोटिस तामील के बाद भी पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 से जुड़े मामले में आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुड़ने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान सचिव सभी जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में नोटिस जारी करने के बाद उनकी तामील में हो चुकी है, लेकिन आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और केस के अंजोइसी भी हाज़िर नहीं हुए। ऐसे में आयोग सचिव इस संबंध में अपना उचित स्पष्टीकरण दें।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर

पांच आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों को दुबई से संचालित नंबरों के माध्यम से सट्टेबाजी के लिए आईडी (लाइन) उपलब्ध करवाई जा रही थी। पुलिस अब इस मामले में दुबई कनेक्शन की भी गहन जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए

अजमेर निवासी साहिल खान के साथ नागौर निवासी इब्राहिम खान, दीलत अली, इमरान खान और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 5० से अधिक बैंक खाते मिले हैं। जिनमें सट्टेबाजी की रकम द्वांसफर की जा रही थी। पुलिस ने इन खातों में करीब दो लाख रुपये की रकम होल्ड भी करवा दी है।

मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम

■ **राजस्थान में 10 जनवरी से कांग्रेस का हल्लाबोल**

राजनीति में यह मुद्दा शहर से लेकर गांव की चौपालों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में लंबे समय से फर्जीबाड़ा और भ्रष्टाचार फल-फूल रहा था। फर्जी जांब कार्ड सरपंचों के पास मिलते थे और मजदूरों के हक का पैसा बिचौलिया खा रहा थे।

नए कानून के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाए हुए पारदर्शिता लाई गई है। सरकार ने रोजगार के दिन 1०0 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। राठौड़ ने कहा कि आजीविका मिशन के शब्दों को जोड़ने से यदि नाम नाम बन गया, तो इस पर आपत्ति करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि 2००4 से अन्न तक खर्च हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये में से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले बीजेपी सरकार ने खर्च किए हैं।

बकाया नगरीय विकास कर की वसूली के लिये टीम अलर्ट मोड पर

जयपुर। नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सेनी के निर्देशानुसार मानसरोवर जोन में नगरीय विकास कर की बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। इस क्रम में बुधवार को सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में स्थित कुल 6 संपत्तियों पर बकाया नगरीय विकास कर की राशि की वसूली की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी, प्रशासनिक एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर बकाया राशि जमा कराने हेतु कुर्क क की प्रक्रिया अपनाई गई। जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम द्वारा बकायादारों पर कुर्क की कार्रवाई की गई जिसमें दो संपत्तियों पर कुर्क की गई तथा शेष चार प्रकरणों में वारंट/कुर्क से पूर्व ही समझौदा के दौरान 11 लाख 71 हजार 998 रुपये बकाया नगरीय विकास कर जमा कराया गया।

इसके अतिरिक्त झोटवाड़ा, वैशाली नगर जोन में भी राजस्व शाखा द्वारा 6 सम्पत्तियों पर नगरीय विकास

■ **आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुड़ने के आदेश दिए**

अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 18० पदों भर्ती निकाली थी। जिसमें मुख्य परीक्षा में करीब तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं आयोग ने इनमें से सिर्फ 4 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया और आयोग के परिणाम के अनुसार अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम अनिवार्य चालीस फीसदी अंक भी नहीं ला सके। याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में चालीस फीसदी से अधिक अंक हासिल किये थे। आरजेएस परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा से कहीं अधिक कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में असफल कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम ममाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में आशंका जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर अंकन कर मपीनी अंदाज में कोर्पाया जांची गई है। ऐसे में परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए।

मनरेगा पर आलाकमान की भाषा बोल रहे सीएम : टीकाराम जूली

■ **जूली ने कहा कि, जिस व्यवस्था ने उन्हें पहचान दी, आज उसे ही कमजोर करने में वे केंद्र का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक विद्रोहसघात है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद दिल्ली के आलाकमान की भाषा बोल रहे हैं**

करने के बजाय केवल दिल्ली के संदेशवाहक बनकर रह गए हैं।

जूली ने कहा कि, अब तक मनरेगा का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब इसे 6०:4० के अनुपात में बांटकर राज्यों पर 40 प्रतिशत फंड का बोझ डालना तानाशाही है। इससे राजस्थान के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होगा। यह सोधे तौर पर संघीय ढांचे को नष्ट करने की साजिश है।

जूली ने कहा- वीबी जी राम जी केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि मनरेगा के मूल सिद्धांतों पर हमला है। मनरेगा

एक कानूनी अधिकार था, जबकि नई योजना इसे केंद्र की मजी पर निर्भर बनाना चाहती है। मनरेगा ने गांवों में रोजगार देकर पलायन रोका और महिलाओं को आर्थिक संबल दिया। भाजपा को गांधी और मनरेगा, दोनों खटकते हैं, इसलिए इस हक को छीनने की साजिश रची गई है।जूली ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली की कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश के गरीब मजदूरों के हक की बलि चढ़ा देंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस निचविरोधी नीति का सदन से लेकर सड़क तक कड़ा विरोध करेगी।

सार-समाचार

विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आज से

जयपुर । विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 8 व 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक संजीव कुमार नाजरी राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा होंगे। गृह राज्य मंत्री जगवह सिंह बेदाम, मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए.सावंत, उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा व जयपुर मुख्यालय पर युद्धस्थापित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा सभी रेंज आईजी, सभी जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 12 जनवरी 195० को नई दिल्ली में किया गया। इसी क्रम में 60 वाँ राष्ट्रीय डीजी/आईजी पुलिस सम्मेलन नवम्बर 2०25 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। जिसकी सिफारिशों के अनुक्रम में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में ०2 दिन में दस सत्र आयोजित होंगे। जिनमें विकसित भारत में पुलिसिंग सम्बन्धी विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे।

जयपुर केंद्रीय कारागार में फिर मिला मोबाइल फोन

जयपुर। घाटगेट स्थित केंद्रीय कारागार में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जेल परिसर से मोबाइल फोन बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची लाल कोठी थाना पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर उसके ईएमआई नंबर और सिम नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने वार्ड नंबर-7 की बैक नंबर-3 में स्थित टॉयलेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टॉयलेट में छुपाकर रखा गया एक की-पैड मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ। इसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना लालकोठी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेल कारापाल अशोक कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात बंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन के ईएमआई नंबर और सिम कार्ड के माध्यम से यह पता लगाने में जुटी है कि मोबाइल किस बंदी का है और जेल के भीतर यह कैसे पहुंचा।

जल जीवन मिशन घोटाले में जांच का दायरा सीमित क्यों

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही जांच को सिर्फ दो फर्मों तक सीमित रखने के मामले में ईडी और राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। एक्स्ट्रा सीजे सजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक ऑफेंस करणन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। इसके बावजूद भी केवल दो टेका फर्म के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर जांच की गई है। याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी, लेकिन केवल दो फर्मों के अलावा अन्य की ओर से किए गए

■ **याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी**

फर्जीबाड़े की न तो जांच की गई और ना ही अब तक एफआईआर दर्ज की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मामलों में प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने के लिए मामले को सुनवाई तीन सप्ताह बाद करना तय किया है।

भरतपुर में बीएसएनएल ऑफिस में आग लगी, ट्रांसमिशन रूम जलने से नेटवर्क ठप

बीएसएनएल के ट्रांसमिशन रूम में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है

भरतपुर, (निसं)। शहर के कृष्णा नगर स्थित बीएसएनल ऑफिस में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कम्प मच गया। आग लगने से विभाग को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान पर आ गया। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि नुकसान काफी हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी दमकल गाड़ियों काफ़ी देरी से पहुंची। बाद में भरतपुर की चार दमकल गाड़ियों के अलावा उच्चैन एवं नदबई नगर पालिका से दमकलें बुलाई गईं। आगजनी से बीएसएनल का नेटवर्क ठप हो गया और एक लाख से अधिक मोबाइल नेटवर्क और बैंक लाइन सीज हो गई।



भरतपुर में बीएसएनल ऑफिस में आग लगने से धुआं ही धुआं हो गया।

लगने की बड़ी घटना घटित हो चुकी है। बताया गया कि बीएसएनल के पास न तो फायर एनओसी थी, साथ ही आग बुझाने के यंत्र भी एक्सपायर थे, इसलिए नगर निगम ने बिल्डिंग सीज करने के नोटिस दिए थे। वहीं बीएसएनल के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के करीब 45 मिनट बाद दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची।

बीएसएनएल सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेखर एवं ब्रजभूषण पाराशर ने बताया कि बीएसएनएल के

ट्रांसमिशन रूम में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन, दमकल की गाड़ियां एक घंटे की देरी से ही आईं। उसमें भी पानी पर्याप्त नहीं था। आग से विभाग को काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग के अंदर जाकर सभी चीजें देखी जाएंगी उसके बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। नगर निगम के राजस्व अधिकारी तेजराम मीणा ने बताया कि फायर स्टेशन पर 2 बजे

करीब आग लगने की सूचना मिली थी। बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट की जानकारी की गई तो, वह भी एक्सपायरी डेट के थे। फायर एनओसी नहीं होने के कारण नगर निगम ने बिल्डिंग सीज के नोटिस बीएसएनल को दिए थे। इसके साथ ही बीएसएनल ऑफिस की तरफ से यूटी टैक्स भी जमा नहीं करवाया गया था।

पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. सुभाष

गर्ग ने कहा कि भरतपुर के बीएसएनएल

आफिस में लगी आग की घटना की

डीडवाना : ग्राम पंचायत कोयल को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध जारी

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना जिले में ग्राम पंचायतों के नए सिरे से पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर जगह-जगह विरोध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में लाडनू उपखंड की ग्राम पंचायत कोयल को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध होने लगा है। इसके तहत बुधवार को ग्राम बादेड़ व बेड़ के सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत मुख्यालय ग्राम बादेड़ को बनाने की मांग की।

इस दौरान बादेड़ ग्राम की महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं ने राजस्थानी गीत गाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बादेड़ को मुख्यालय नहीं बनाने पर भूख हड़ताल करने तथा मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया कि राज्य सरकार ने नवसृजित ग्राम पंचायत

- ग्राम बादेड़ व बेड़ के सैकड़ों लोग कलैक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत मुख्यालय ग्राम बादेड़ को बनाने की मांग की**
- बादेड़ को मुख्यालय नहीं बनाने पर भूख हड़ताल करने तथा मतदान का बहिष्कार की चेतावनी दी**
- पिछले चार दिन से उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने ग्रामीणों का धरना जारी है**

कोयल का गठन किया है, जिसमें ग्राम बेड़ व बादेड़ को भी शामिल किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल को बनाया जाने से ग्राम बादेड़ व बेड़ के आम नागरिकों में भारी विरोध है। उन्होंने बताया कि ग्राम बादेड़, ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल से जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा गांव है। आबादी घनत्व एवं वोटर लिस्ट के अनुसार भी ग्राम बादेड़ में मतदाता संख्या भी ज्यादा है। इसके अलावा नवसृजित ग्राम पंचायतों में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गांव ही पंचायत मुख्यालय बनने के कानूनी दृष्टि

से हकदार भी है। इसी प्रकार ग्राम बादेड़ मेधा हाईवे व आस-पास के गांवों के सम्पर्क सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। गांव में सरकारी भूमि की भी पर्याप्त उपलब्धता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आधुनिक सुविधाओं से लेस सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, जो गांव के बीच आबादी में पर्याप्त जगह पर बना हुआ है। इसके अलावा भी गांव शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बादेड़ से कोयल की दूरी करीब 8 किमी है और

ग्राम बादेड़ से कोयल की सीधी सड़क की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ग्राम बादेड़ पहले बाकलिया ग्राम मुख्यालय से जुड़ा हुआ था जो करीब 1.5 किमी दूर था और अब कोयल मुख्यालय बना देने से बादेड़ अब 8 किमी दूर हो गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में सरकार को जो पत्र भेजा गया था, उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय बादेड़ को रखने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल को केवल मात्र राजतैनिक ढ़पेत से बनाया गया है। जिसमें राज्य सरकार से जारी नियमों को पूर्णतया ताक में रखा गया है, जिसमें केवल आनन-फ़ानन में मुख्यालय कोयल ट्रांसफर किया गया है, जबकि ऐसी कोई भी अहंता ग्राम कोयल पूरी नहीं कर रहा है और मजबूरन ग्रामवासियों को सारे जापन देने के उपरान्त और कोई कार्रवाई नहीं होने पर 4 जनवरी से उपखण्ड कार्यालय के सामने धरना देने को विवश होना पड़ रहा है।

चोरी के आरोप में दो गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की रायपुर थाना पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बोरणा के भैरुजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है।

रायपुर पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनदास वैष्णव और पुष्पा देवी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से मंदिर से चुराया गया गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2025 की रात को चोरों ने बोरणा गांव के कोयड़ स्थित भैरूजी मंदिर और माताजी मंदिर को निशाना बनाया था। चोरों ने ताला तोड़कर वहां से चांदी के दो छत्र, एक नथ और गैस सिलेंडर चोरी कर लिया था। इस संबंध में 1 जनवरी को परिव्रादी भीपू गुर्जर ने मामला दर्ज करवाया था। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर रायपुर थानाधिकारी शंभु दयाल की टीम ने तत्कनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

वाहनों में तोड़फोड़ करने वाला बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। शहर पुलिस ने सूरजपोल थाना क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले शांति बदमाश को गिरफ्तार किया व विधो से संघर्षरत दो बाल अपचारियों को डिटोन किया।

प्रकरण के अनुसार 6 जनवरी रात में सूरजपोल थाना क्षेत्र स्वराजनगर माछला मगरा क्षेत्र में गली में रोड़ किनारे खड़ी करीब 2 दर्जन गाड़ियों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ करने की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप

अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह चौहान मय टीम ने मामले में नवाज पुत्र जावेद खान उर्फ लाला निवासी दिवानशाह कॉलोनी व साथियों द्वारा करने की जानकारी जुटाई। इस मामले में आरोपियों के ठिकाने पर दबीश दी तो तीनों माछला मगरा से पुलिस को देख भागने के लिए पहाड़ी से कूद पड़े, जिससे नवाज के दोनों पांव व एक हाथ टूट गया तथा शेष दोनों के पैर टूटे है। जिन्हें डिटोन करने के बाद चिकित्साल में उपचार करवाया तथा नवाज को गिरफ्तार किया।

बीकानेर, (निसं)। बाइक पर सवार होकर मुक्ताप्रसाद नगर के सेक्टर 10 में पहुंचे बदमाशों ने पांच लाख रुपए की फिरोती के लिए घर के आगे खड़ी एक कार में आग लगा दी और धमकी देकर फरार हो गए। सोमवार की रात को करीब 2.30 बजे बाइक पर सवार होकर मुक्ताप्रसाद नगर के सेक्टर 10 में पहुंचे बदमाश रेलवे कर्मचारी श्यामसुन्दर सोनी के घर पहुंचे। घर के आगे खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस दौरान शोर सुनकर घर के लोग बाहर आए तो बदमाशों ने पांच लाख रुपए नहीं

- आरोपियों ने 23 दिसंबर को व्हाट्सअप मेंसेज कर 5 लाख की फिरोती मांगी थी**

देने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। इतला मिलने पर मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।

श्यामसुन्दर सोनी की ओर से

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लुकमान व 3-4 अन्य ने 5 लाख रुपए की फिरोती के लिए उसके घर के आगे खड़ी कार को जला दिया और जान से मारने की धमकी दी है। श्यामसुन्दर सोनी ने बताया कि आरोपियों ने 23 दिसंबर को मोबाइल पर व्हाट्सअप मेंसेज कर 5 लाख रुपए की फिरोती मांगी थी। उसने रकम नहीं दी और मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया था जिसकी जांच चल रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थानों में और भी मुकदमे दर्ज हैं।

केकड़ी में दिनदहाड़े फायरिंग, प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर घायल

- आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की, पेट और हाथ में गोली लगने से प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर रूप से घायल**

- पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय साहू को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया**

देने के बाद आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अजय साहू को घटनास्थल के पास ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसके दो अन्य साथियों को बाद में पुलिस ने डिटोन कर लिया।

घायल व्यापारी को आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मौल और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा पुलिस जांबे के साथ अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।

एएसपी राजेश मौल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से

आर्थिक लेनदेन को लेकर रंजिश चली आ रही है। पूर्व में भी दोनों ओर से मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार विवाद पिछले कुछ दिनों से और गहराता जा रहा था तथा कुछ समय पहले पीड़ित के छोटे पुत्र पर भी हमला किया गया था। पूर्व घटनाओं के बावजूद विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका, जिसके चलते मामला बुधवार को हिंसक रूप ले बैठा। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और वारदात में उसके साथ कौन-कौन शामिल था। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

डीडवाना कलैक्टर ने 70 चिकित्सा केंद्रों को पट्टे दिये

डीडवाना, (निसं)। जिला कलैक्टर डॉ.महेन्द्र खड़गावत ने बुधवार को जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्यकेंद्रों के 70 पट्टे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को प्रदान किये। अतिरिक्त जिला कलैक्टर मोहन लाल खटनाबलिया ने बताया कि जिला कलैक्टर डॉ. खड़गावत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कुल 70 पट्टे प्रदान किये हैं।

उन्होंने बताया कि जिला कलैक्टर द्वारा जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की भूमि के पट्टे जारी करने के निर्देश दिए प्रदान

किये थे। पूर्व में जिला कलैक्टर द्वारा जिले के 13 चिकित्सा संस्थानों व कार्यालयों को पट्टे प्रदान किये गए थे, इसी क्रम में बुधवार को जिले के 70 चिकित्सा केंद्रों को पट्टे जारी किये गए हैं। अतिरिक्त जिला कलैक्टर ने बताया कि चिकित्सा केंद्रों को पट्टे मिलने से स्वास्थ्य संस्थानों के भवन निर्माण एवं क्रमोन्त होने पर उनके विस्तार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कलैक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन के साथ- साथ त्वरित अग्रिम कार्यवाही कर पट्टे जारी करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।

गुड़ामालानी को बाड़मेर और बालोतरा जिलों में बांटने से लोगों में आक्रोश

- गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायत समितियों को बाड़मेर में रखा गया है, जबकि कुछ को बालोतरा जिले में जोड़ा गया है**

- कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है**

को असमंजस में डाल दिया है। एक तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए लिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए लिया है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दो जिलों में बांटना यह न्याय संगत नहीं है। बालोतरा जिले से लम्बी दूरी तय करने वाले मतदाताओं का कहना है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को एक ही जिले में रखा जाए। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को दो भागों में बांटने के फैसले ने जनता

होती नजर आ रही है। गौरतलब है कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को पूरा बालोतरा जिले में नहीं लेकर कुछ ग्राम पंचायतों को हटाकर बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। बालोतरा जिले से कम दूरी वाली ग्राम पंचायतों को बाड़मेर जिले में जोड़ना जबकि धोरीमन्ना बालोतरा से लम्बी दूरी है, उसको बालोतरा जिले में शामिल करना इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर पांचवें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं लगातार चल रहे धरने में दिनों-दिन लोगों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है।

छह लाख रुपये का डोडा-चूरा सहित दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान 47 किलो डोडा-चूरा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई में पकड़े गये अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा की अनर्गलष्टीय कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है, पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त बोलeros को भी जब्त किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों

की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अभियान के तहत कनवास थाने के उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि विशेष टीम ने कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की चौकियों की, पुलिस चौकियां के दौरान एक बोलeros पिकअप को

रोककर तलाशी ली तो बोलeros पिकअप से अवैध मादक पदार्थ 47 किलो डोडा-चूरा तस्करों के लिये ले जाते हुए बरामद किया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट में हिमाचल प्रदेश के गणजी निवासी शबीर खान एवं जिला पंजाब के जमालपुरा बस्ती निवासी लियाकत अली को गिरफ्तार किया। पकड़े गये दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

हाईकोर्ट ने टीएसपी एरिया में नगर पालिका बनाने को हरी झंडी दी

में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। दरअसल, राज्य सरकार ने उदयपुर के बलीचा, ऋषभदेव, सेमारी और बांसवाड़ा के घाटोला, परतापुर सहित कई गांवों को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था। ग्राम पंचायत बलीचा की सरचक्क लक्ष्मी बाई गम्पती और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243-जेडसी के तहत टीएसपी क्षेत्रों में नगर पालिका कानून नहीं होता। उन्होंने दलील दी कि पेसा एक्ट की तरह नगर पालिकाओं के लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, इसलिए राज्य सरकार इन क्षेत्रों में नगर पालिका गठित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी

और पेसा एक्ट का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, वहां राज्य के सामान्य कानून (जैसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 2009) लागू होने से नहीं रोके जा सकते। जब तक राज्यपाल 5 वीं अनुसूची के तहत किसी कानून को विशेष रूप से रोकने की अधिसूचना जारी नहीं करते, तब तक विकास और शहरीकरण के लिए म्युनिसिपैलिटी एक्ट लागू रहेगा। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि 2001 में प्रस्तावित एम्पईएसए बिल आज तक संसद से पास नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस 'संवैधानिक वैक्यूम' को भरा जाना जरूरी है। आदेश की प्रति केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द कानून बनाया जा सके।

